PROF. MADHU DANDAVATE: I made a very important point about the service to Andaman and Nicobar.

SHRI H. M. TRIVEDI: It is quite true that the Shipping Corporation of India, which runs the Andaman and Nicobar service, also makes a loss on that particular service, but negotiations, in fact, are now going on, both for the purpose of rationalisation of the services so that losses would diminish and also for adjustment of fares both on passengers and on cargo, so that again the losses could be minimised.

PROF. MADHU DANDAVATE: I may tell the hon. Minister that if we do not get justice on the floor of the Lok Sabha, from the 14th March there will be a massive agitation started all along the coast of Konkan.

MR. SPEAKER: God help these agitations—they are everywhere.

SHRI R. P. SHENOY: May I know whether it is a fact that not a single steamer passenger service in the country is running at a profit at present? Since it is absolutely necessary to have coastal shipping, would Government consider giving more subsidies to enable the coastal shipping lines to continue?

SHRI H. M. TRIVEDI: As a general proposition it is true that passenger services are not making profits. There are only two major passenger services in the country—the Konkan service and the Haj pilgrim service. As far as subsidy is concerned, I do not see how a commercial public undertaking like the Moghul Lines can be expected to run at a loss.

**श्री जगन्नाथ राव जोशी** : अध्यक्ष जी, यह जो कोंकन स्टीमर सर्विस है, जब इस को चोगले चलाते थे तब उन्होंने 39 परसेन्ट वृद्धि की मांग की थी, किन्तु भावे कमीशन ने 20 प्रतिशत वृद्धि की सिफारिश की थी। इस लिए सरकार ने उस कम्पनी को अपने हाथ में लिया और खुद 30 प्रतिशत किराया बढ़ाया और आज इस प्रश्न के अनुसार 130 प्रतिशत तक किराया बढ़ाया, ऐसी स्थिति में इसका समर्थन कैसे किया जा सकता है—यह तेल की वृद्धि के कारण हुआ है या मिसमैनेजमेन्ट के कारण हुआ है— इसका क्या आधार है ?

SHRI H. M. TRIVEDI: I think I have already answered the question in terms of fuel costs which have risen over the period from May 1973 to December 1974.

**नागपुर में आयोजित विश्व हिन्दी सम्मेलन**

*43 **श्री शंकर दयाल सिंह** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1975 के दौरान नागपुर में आयोजित विश्व हिन्दी सम्मेलन में भाग लेने के लिए किन-किन देशों से कितने प्रतिनिधि भारत आये;

(ख) क्या नागपुर विश्व हिन्दी सम्मेलन में आये विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने यह मांग की थी कि संयुक्त राष्ट्र संघ में हिन्दी को स्थान दिलाने के लिए भारत को पहल करनी चाहिए ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI BIPINPAL DAS): (a) 75 delegates from 30 countries visited India to participate in the World Hindi Convention. A list of the countries has been laid on the table of the House.

(b) and (c). A proposal asking for the acceptance of Hindi as one of the Official Languages of the U.N. was adopted by acclamation by the Convention. Government considers this as a welcome development. Government has also taken note of the sentiment expressed in this regard in the House. Accordingly, our Parliament Representative in New York has been instructed to consult with other delegations. On

the basis of responses received and an assessment of the possibilities, further action, as necessary will be taken.

LIST OF PARTICIPATING FOREIGN COUNTRIES IN THE WORLD HINDI CONFERENCE HELD IN NAGPUR

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bangaladesh | 16 | Sri Lanka |
| 2 | Belgium | 17 | Mauritius |
| 3 | Burma | 18 | Mangolia |
| 4 | Canada | 19 | Netherlands |
| 5 | Czechoslovakia | 20 | Poland |
| 6 | Denmark | 21 | Sweden |
| 7 | Fiji | 22 | Thailand |
| 8 | France | 23 | Trinidad |
| 9 | G.D.R. | 24 | U.K. |
| 10 | F.R.G. | 25 | U.S.A. |
| 11 | Guyana | 26 | U.S.S.R. |
| 12 | Hungary | 27 | Yugoslavia |
| 13 | Iran | 28 | South Africa |
| 14 | Italy | 29 | Surinam |
| 15 | Japan | 30 | Nepal |

**श्रीमती टी० लक्ष्मी कातम्मा :** अध्यक्ष महोदय, कम से कम इस प्रश्न का जवाब तो हिन्दी मे दिया जाना चाहिए था।

**श्री शकर दयाल सिंह :** अध्यक्ष जी, मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है उससे यह पता चलता है कि नागपुर में जो विश्व हिन्दी सम्मेलन हुआ उस मे 30 देशों के लगभग 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अखबारों के अनुसार प्रतिनिधियों की सख्या 200 से अधिक थी, लेकिन सरकारी उत्तर मे 75 है—मै फिलहाल सरकार की इस बात को मान लेता हू। मैं सरकार से जानना चाहता ह—सयुक्त राष्ट्र सघ मे हिन्दी को स्थान मिले, इस के लिए क्या सरकार उन देशो मे भी सहायता लेगी जिन के प्रतिनिधि नागपुर विश्व हिन्दी सम्मेलन मे उपस्थित थे, जिन के यहा हिन्दी बोली और समझी जाती है, क्योंकि वहा पर उपस्थित सभी देशों के प्रतिनिधियों ने यह मांग की थी कि भारत को इस का अगुआ बन कर पहल करनी चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ में हिन्दी को स्थान मिले क्योंकि यह विश्व में तृतीय सब से अधिक लोगों की बोलने वाली भाषा है। मैं सरकार से यह भी जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में भारत सरकार कौन सी पहल कर रही है और क्या उन देशों से भी सहायता मागेगी जो हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र सघ मे स्थान दिलाने के काम में सहयोग देने को राजी हैं ?

**एक माननीय सदस्य :** उत्तर हिन्दी में आना चाहिए, मंत्री महोदय हिन्दी जानते है—हैदराबाद में उर्दू में भाषण दे चुके है।

**श्री विपिनपाल दास :** मैं हिन्दी में जरूर बोल सकता हूं, लेकिन कभी कभी वर्ड्स में गडबड़ हो जाती है, फिर भी मैं कोशिश करूगा। नागपुर में जो लोग सम्मेलन में आये थे, उनमे सरकारी तौर पर सिर्फ मोरिशस का डेलीगेशन था, बाकी जितने लोग थे, वे नान-आफिशियल थे और यह कन्वेशन भी नान-आफिशियल बेसिज पर हुआ था। जो लोग नागपुर आये थे वे सरकारी अथारिटी ले कर नही आये थे, जो कुछ वहा पर बोले वह सरकार को रिप्रेजेण्ट नही करता है।

हमारे जो रिप्रेजेण्टेटिव न्यूयार्क मे हैं, हम ने उन को लिखा है कि वे सब देशो के साथ सलाह करे, उस के बाद हम देखेंगे कि हमे कितने देशों से मदद मिलेगी, उन के रेस्पोंस की हमे जो रिपोर्ट मिलेगी उस के बेसिज पर हम आगे कदम उठायेगे।

**श्री शंकर दयाल सिंह :** अध्यक्ष जी, मैंने यह नही कहा था कि जो प्रतिनिधि वहा आये थे, वे सरकारी तौर पर आये थे। मैंने कहा था कि इतने देशों के प्रतिनिधियों ने उस में भाग लिया था। जहा तक हमारी सरकार की बात है—हमारी प्रधान मत्री जी ने उसका उद्घाटन किया था, मौरिशस के प्रधान

मंत्री श्री शिवसागर रामगुलाम जी ने उसकी अध्यक्षता की थी, चार-पांच केन्द्रीय मंत्री भी वहां शामिल हुए थे। महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री श्री नायक उस के स्वागताध्यक्ष थे। 20 संसद् सदस्य भी उस में गये थे, जिन में हमारे श्री रामसहाय पाण्डेय जी भी जरूर होंगे।

हमारे डा० कर्ण सिंह जी ने, जो कि वहां मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे, अभी मुझे एक स्लिप भेजी है जिस में उन्होंने कहा है कि नागपुर में मैंने सर्वप्रथम मांग की थी कि हिन्दी को यू० एन० ओ० में स्वीकृति मिलनी चाहिए। इस के आधार पर मैं आज डा० कर्ण सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वे भी आज सदस्य के रूप में एक सप्लीमेण्ट्री जरूर पूछें।

मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने जो उत्तर दिया है, उस सम्बन्ध में आप ने संयुक्त राष्ट्र संघ में जो हमारे स्थायी प्रतिनिधि है उन को कब पत्र लिखा, किस आशय का पत्र लिखा, कृपया वह पत्र पढ़ कर सुनाया जाय और क्या आप ने यह भी लिखा है कि इस का उत्तर वे आप को कब तक दे और जब वह उत्तर आयेगा तो क्या उस उत्तर को सदन के सामने रख कर आप सदस्यों को भी उस की जानकारी देंगे ?

**श्री विपिनपाल दास :** पिछले सेशन के दौरान यहां पर सदस्यों ने जो विचार जाहिर किये थे उस को ले कर हमने अपने परमानेन्ट रिप्रेजेन्टेटिव को लिखा था। 8 जनवरी को नागपुर में जो विश्व हिन्दी सम्मेलन हुआ था, उस के पहले ही हम उन को लिख चुके थे, इस हाउस की प्रोसीडिंग्ज भी हम ने उन को भेजी और बाद में नागपुर में जो फंक्शन हुआ उस की रिपोर्ट भी हम ने उन को भेजी। हमने कोई लिमिट तय नहीं की थी कि उस तारीख तक हम को वे अपनी रिपोर्ट भेज दें, जितनी जल्दी वे अपना असेसमेन्ट कर सकेंगे हम को जरूर भेजेंगे। जो पत्र हम ने उनको लिखा था वह पत्र इस वक्त मेरे पास नहीं है।

**श्री शंकर दयाल सिंह :** यू० एन० ओ० में आप ने जिन को पत्र भेजा है, वे हिन्दी जानते हैं या नहीं ?

**श्री विपिनपाल दास :** हम ने अपने रिप्रेजेन्टेटिव को भेजा है।

**श्री शंकर दयाल सिंह :** मैं यही पूछ रहा हूं—वे हिन्दी जानते है या नहीं ? हमारे जो रिप्रेजेन्टेटिव यू० एन० ओ० में है, वे हिन्दी जानते हैं या नहीं ?

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी :** जिस दिन हिन्दी को हम ने राष्ट्र भाषा बनाया, मानों हिन्दी को राष्ट्र को सौंप कर, उसे राजकाज की भाषा बनाने की जिम्मेदारी से हम मुक्त हो गये। अब ऐसा लगता है कि हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र को सौंप कर उस को भारत में प्रतिष्ठित करने की जिम्मेदारी से हम बचना चाहते है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं—क्या विदेशों में जो हमारे राजदूतावास है, उन को भी हम ने यह सलाह दी है कि वे जिन देशों में स्थित है वहां की सरकारों से संयुक्त राष्ट्र संघ में हिन्दी को स्थान दिलाने के बारे में बातचीत करें और क्या हम इस बात का भी प्रयत्न करेंगे कि केवल भारत ही नहीं, मौरिशस, नेपाल और अन्य देशों में जहां हिन्दी बोलनेवालों की संख्या बहुत बड़ी है उन देशों की सरकारों का सहयोग प्राप्त करें जिससे कि हिन्दी के पक्ष को अधिक बल मिल सके ?

**श्री विपिनपाल दास :** हमने यह इंस्ट्रक्शन जरूर दी है कि हिन्दी का इस्तेमाल किया जाय, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि सभी काम हिन्दी में ही किया जाय, जहां तक पासिबल हो हिन्दी का इस्तेमाल किया जाय।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी :** अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह नहीं था। दूतावासों में

कितनी हिन्दी चल रही है, मुझे मालूम है, मैं उसकी चर्चा यहां करके इस समय इस प्रश्न को बिगाडना नही चाहता । दुनिया के जो प्रतिनिधि यहां आये थे, वे हिन्दी मे बात करते थे, लेकिन भारत मे अंग्रेजी के साम्राज्य को देखकर उन्होने हमको ताने दिये । मैने पूछा था कि हमारे जो दूतावास अन्य देशो मे है क्या वे भी कोशिश करेगे उन देशो की सरकारो से बात करने के लिये ।

**श्री विपिनपाल दास :** यह हमारे दिमाग मे है । जब न्यूयार्क से असेसमेंट मिल जायगा तो यह भी दिमाग मे है कि हर कैपिटल मे कोशिश की जायगी । लेकिन पहले न्यूयार्क से असेसमेंट मिल जाय ।

**श्रीमती टी० लक्ष्मीकान्तम्मा :** उप मत्री महोदय ने कन्वेंशन के आफिशियल या नान-आफिशियल कैरेक्टर की बात की । जब कि यह बात नही है क्योकि सोवियत यनियन हिन्दी का कट्टर समर्थक है । जो भी भारत से सोवियत यनियन जाते है । और वहा अंग्रेजी बोलत है उसका सोवियत यनियन वाले पसन्द नही करते है । यहा के लोग हिन्दी मे बोले इस बात का वह पसन्द करते है । मेरे ख्याल मे पिछले राष्ट्रसघ म हिन्दी को मान्यता दिलाने के लिये हमारी सरकार न पूरे कदम नही उठाये हैं । हिन्दी सम्मेलन मे जब हर एक देश के प्रतिनिधि ने हिन्दी को राष्ट्रसघ मे मान्यता देने का समर्थन किया है तब कम से कम आप इस बारे मे पूरे कदम उठायेगे ?

**श्री विपिनपाल दास :** हमने तो न्यूयार्क मे अपना प्रतिनिधि का इन्स्ट्रक्शन दिये है to make an assessment On the basis of that assessment, we will take steps

**श्री राम सहाय पांडे :** अध्यक्ष जी विश्व हिन्दी सम्मेलन नागपुर मे सम्पन्न हुआ यह एक ऐसी ऐतिहासिक घटना थी जिस का हम स्वागत करते है । कदाचित इस प्रकार का सम्मेलन अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार हुआ जिसमे तीस देशो के लोगो ने भाग लिया और उनमे यू रोप के करीब करीब आधे प्रतिनिधि थे । उन सबने बडी परिष्कृत हिन्दी बोलते हुये कहा और उनकी यह राय थी कि जिस प्रकार चर्चिल ने परिकल्पना की थी कि अंग्रेजी भाषा का एक मच बनाया जाय उसी प्रकार क्यो नही हम भी 30 देशो के प्रतिनिधियो के इस विचार का स्वागत करे कि हिन्दी भाषा का एक मच स्थापित हो जिसमे हिन्दी भाषा स्थापित हो । सूर्यनाम की श्रीमती कमला जगमोहन ने उस विश्व सम्मेलन मे यह कहा था कि यदि हमारे बुजुर्ग रामायण का गुटका अपने साथ मे ले जाते तो भारतीय सस्कृति वहां समाप्त हो जाती । यह कहकर वह विह्वल हो कर रो पडी । जब एक प्रकार के मच की वहा कल्पना की गई और सयुक्त राष्ट्रसघ मे हिन्दी भाषा को स्वीकृति का समर्थन किया, और जर्मनी, फ्रास इगलैंड और रूस हमारे साथ है तब क्या हम इस प्रश्न का गम्भीरता के साथ लेगे और यू० एन० ओ० मे हमारी भाषा स्वीकृत हो इसके लिये अधिकाधिक प्रयास विश्व हिन्दी सम्मेलन के प्रस्ताव के अर्न्तगत करेगे और उस दिशा मे गम्भीरतापूर्वक कदम उठायेगे ।

**श्री विपिनपाल दास :** Such a matter can be better taken up more on a non-official basis than on an official basis. यह जो हिन्दी कन्वेंशन हुआ यह नान-आफिशियल बेसिस पर हुआ । फिर भी हमने उस मे मदद की उस सम्मलन के लिये पैसा दिया । लेकिन इनीशियटिव जो लेना है वह नान-अफिशियल पर होने से ज्यादा अच्छा होगा यह हमारा ख्याल है ।

**श्री एस० एम० बनर्जी :** अध्यक्ष महोदय, मत्री जी ने जो जवाब दिया मै समझता हू कि सतोषजनक नही है इस कारण से कि उन्होने यह कहा कि उस सम्मलन मे नान-आफिशियल लोग आये थे, वह आफिशियल नही थे । सवाल यह नही था । सवाल यह था कि इतने देश

आये थे, और क्या यह बात सही है कि हमारे नुमाइन्दे जो यू० एन०ओ० की जनरल असेम्बली मे भाषण देते है वह भी अंग्रेजी मे देते हैं, भले ही वह गलत अंग्रेजी हो । तो क्या सरकार इस बात का आश्वासन देगी कि हमारे नुमाइंदे हिन्दी मे बोलेंगे क्योंकि अगर हिन्दी मे भाषण देना शुरू करे तो हिन्दी को स्वीकृति मिल सकती है । चूंकि भाषण अंग्रेजी मे दिया जाता है और लोग समझते है कि वही पढे लिखे लोग है जो अंग्रेजी बोलते है, तो यह एक प्रकार से कलंक का टीका हमारे लिये है । तो क्या मंत्री जी यह आश्वासन दे सकते है कि आइन्दा डेलीगेशन हिन्दी जानने वालो का ही होगा और यू० एन० ओ० मे हिन्दी मे ही भाषण दिया जायगा जिससे हिन्दी की तरक्की हो ?

**श्री विपिनपाल दास** जहा तक हमको मालूम है राष्ट्रसघ मे जब भाषण देते है तो जिन भाषाओं का स्वीकृति मिली हैं उन्ही मे भाषण देते है । हिन्दी भाषा का अभी तक स्वीकृति नही मिली है इसी लिये हिन्दी मे भाषण नही दे सकते । जब हिन्दी को स्वीकृति मिल जायगी तो हिन्दी मे भाषण करेंगे ।

**श्री भागवत झा आजाद** क्या यह बात सही है कि राष्ट्रसघ ने सब से अन्त मे जिस भाषा को यानी अरबिक भाषा को मान्यता दी है उस के बोलने वाले केवल 10 करोड लोग ही है । क्या यह बात भी सही है कि ससार की प्रथम तीन भाषाओं मे, चीनी अंग्रेजी और हिन्दी, ऐसी भाषायें हैं जिन के बोलने वाले ससार मे सब से अधिक है, और इन मे से दो को मान्यता मिल चुकी है । अगर यह बात सही है तो इस आकडे के आधार पर हिन्दी भाषा को मान्यता मिलने मे कोई दिक्कत नही होनी चाहिये । साथ ही विश्व हिन्दी सम्मेलन मे जो सदस्य आये थे चाहे वह गैर-सरकारी सदस्य हो, खासकर जो सोवियत यूनियन के थे जो उन्हो ने वहा बोला क्या हमारी सरकार ने पता लगाया कि उन का मत वहा की सरकार के मत के अनुसार नही था, या वह किस रूप मे अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहे थे । हमारे देश की प्रधान मंत्री और डा० कर्ण सिंह उस सम्मेलन मे किस रूप मे थे ? उनका व्यक्तित्व सरकारी था या गैर-सरकारी था ? मंत्री जी यह कह कर कि यह गैर-सरकारी थे इस की महत्ता को कम कर रहे है या बढा रहे है ? तो आकडे के आधार पर और सोवियत यूनियन, फिजी, मारीशस इन तमाम देशो के प्रतिनिधियों के आश्वासन पर कि वह हिन्दी भाषा को मान्यता दिये जाने के सवाल का समर्थन करेंगे, अब किस बात की कठिनाई है । और क्या असेसमेंट के रूप मे मंत्री जी को चाहिये जब यह सारे देश कह रहे है कि तुरन्त राष्ट्रसघ मे हिन्दी भाषा को मान्यता दी जाए ?

**श्री विपिनपाल दास** : मैं साफ कर देना चाहता हू । एक तो यह कि राष्ट्रसघ मे किसी भाषा को स्वीकृति मिलना इस बात पर निर्भर नही करता है कि कितने लोग उस को बोलते है । बल्कि मेम्बर स्टेट्स, कितने देश उस भाषा को बोलते है, इस पर निर्भर करता हैं । तो यह बात पहले याद रखनी चाहिये ।

**श्री भागवत झा आजाद** : यह आप गलत कह रहे है । चीनी भाषा कितने देश बोलते है, सिर्फ एक देश बोलता है क्या इस का ज्ञान मंत्री महोदय को हैं ।

SHRI BIPINPAL DAS Let me complete my answer. I never made a wrong statement

SHRI BHAGWAT JHA AZAD· You said that it depends upon the number of countries which speak a particular language. Only one country speaks Chinese language. Why then Chinese language has been recognised?

SHRI BIPIN PAL DAS For any language to be recognized by UN, you have to amend the rules of procedure and to get the rules of procedure amended, the majority of the members of UN have to vote for it To-day there are 138 Members in the UN Therefore at least 70 members should vote in our favour.

With regard to the Chinese language it has been accepted from the very beginning because of historical reasons and not at a later stage. So we must have at least 70 member States to support our demand. That is the point I meant and not that it depends upon the number of Hindi-speaking population.

When I said that in the Nagpur Convention, 30 delegations from outside were on non-official basis, I only referred to those who hailed from outside. Excepting Mauritius, all of them were on non-official basis .....

SHRI BHAGWAT JHA AZAD: What do you want to emphasize by that?

SHRI BIPINPAL DAS: I state only the facts.

SHRI BHAGWAT JHA AZAD. Not facts. It shows your attitude.

SHRI BIPINPAL DAS: The main point is that even before the Nagpur Convention, this Ministry and the Government have taken steps to assess the opinion among the Member States in view of the sentiments expressed in this House. We have taken positive steps and unless we get support from 70 Member States, we will not succeed and if we fail it will affect our prestige.

**श्री भागवत झा आजाद** : मंत्री जी के जाने के पहले मैं तीन बार वहां हो आया हूं इसलिये मैं नियमों को जानता हूं ।

**श्री शरद यादव** : अध्यक्ष जी, हिन्दी सम्मेलन की बात चल रही है, जैसे मैं हिन्दी प्रान्त का आदमी हूं, मेरी हिन्दी भाषा है, लेकिन मुझे अंग्रेजी आप का सचिवालय रोज ठूंम ठूम कर भरता है । रोज जो नोटिस आयेंगे वह अंग्रेजी में आते हैं । इससे यह बात साफ जाहिर होती है कि हिन्दी को कोई महत्व नहीं दिया जाता है । जब मैं हिन्दी प्रान्त का रहने वाला हूं तो नियम होना चाहिये कि जिस प्रान्त का आदमी हो उसको उसी भाषा में कागज पत्र दिया जाय और यदि वह न चाहे, तो जबर्दस्ती अंग्रेजी में उस को यह सब दिया जाए । आप मुझे जबरदस्ती अंग्रेजी वाले सवाल क्यों दिये चले जा रहे हैं, अंग्रेजी में नोटिस क्यों दिये जाते हैं । मैं हिन्दी प्रान्त का हूं और मैं चाहता हूं कि मुझे हिन्दी में ही ये चीजें दी जाए ।

SHRI PRIYA RANJAN DAS MUNSI: It is a question to Lok Sabha Secretariat, not to External Affairs Minister.

**अध्यक्ष महोदय** : जो प्रश्न हैं, उस के बारे में आप पूछिये :

**श्री शरद यादव** : मुझे आप अंग्रेजी में ये सब मत दीजिए ।

**श्री जगन्नाथ मिश्र** : श्रीमान, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि विश्व हिन्दी सम्मेलन जो नागपुर में हुआ था, वह शतप्रतिशत सफल हुआ । इस परिप्रेक्ष्य में मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि नागपुर में जो कुछ तथ्यपूर्ण निर्णय लिये गये थे, उन के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार ने क्या कार्यक्रम बनाया है और उस के लिए क्या योजना है ?

SHRI BIPINPAL DAS: I could not follow the question.

**श्री जगन्नाथ मिश्र** : : नागपुर में कुछ तथ्यपूर्ण निर्णय लिये गये थे । मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि उन के कार्यान्वयन के लिये, उन के इम्प्लीमेंटेशन के लिए भारत सरकार की क्या योजना है ?

**श्री विपिनपाल दास** : जहां तक विदेश मंत्रालय का सम्बन्ध है, हमने बताया है कि we welcome the proposal which was passed there and we have also given instruction to our permanent representative in New York to make an assessment.

**श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी** : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या यह सच है कि बंगला देश को जब संयुक्त राष्ट्र संघ में मान्यता देने की बात आई, तो बंगला देश ने बंगला भाषा बोलने के लिए जो मांग रखी थी, वह मंजूर

हो गई और दूसरा प्रश्न यह है कि क्या यह सच है या नहीं कि भारतीय दूतावासों में जो हिन्दुस्तान के बाहर काम करते हैं, दूतावासों के प्रधान को हिन्दी जानना जरूरी है ? अगर नहीं है, तो क्या आई० एफ० एस० में कमीशन द्वारा हिन्दी का पर्चा जरूरी कर दिया जाए ?

**श्री विपिनपाल दास** : दूतावासों में जो काम करते हैं, उन को हिन्दी जाननी चाहिए और जो नहीं जानते है उन के लिए स्पेशल ट्रेनिंग होती है ।

जहां तक संयुक्त राष्ट्र संघ में बंगला भाषा को मंजूरी का प्रश्न है, हमें नहीं मालूम है कि उसको स्वीकृति मिली है या नहीं ।

**अध्यक्ष महोदय** : सारा समय इसी प्रश्न पर लग गया ।

**श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि नागपुर में विश्व हिन्दी सम्मेलन होने से पहले कितनी बार हिन्दी को मान्यता देने के लिए कोशिश की गई थी हिन्दुस्तान की तरफ से और नागपुर सम्मेलन में जो प्रस्ताव पास किया है, उस के बाद क्या कोई ठोस कदम हिन्दी की मान्यता के लिए उठाया गया है । यह साफ जवाब मैं मंत्री महोदय से चाहता हूं ।

**श्री विपिनपाल दास** : इस का जवाब तो मैं पहले दे चुका हूं । इस हाउस के विन्टर सेशन के बाद सब सदस्यों के सेंटीमेंट्स को हम ने नोट किया और जनवरी महीने की 8 तारीख को यह चिट्ठी भेजी थी । नागपुर कन्वेंशन से पहले यह कदम उठाया गया था और जब इस का कोई नतीजा मिल जाएगा, तब दूसरा कदम उठाएंगे ।

**अध्यक्ष महोदय** : मेरी हिन्दी प्रेमियों से प्रार्थना है कि इस प्रश्न पर बहुत समय लग गया है । इसलिए अब अगले प्रश्न पर चलें । आप के प्रेम की हम बहुत कद्र करते हैं । नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री वसंत साठे ।

**Plague Risk as cautioned by Dr. Deoras**

*44. SHRI VASANT SATHE: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY PLANNING be pleased to state:

(a) whether Dr. P. J. Deoras, a member of the World Health Expert Committee on Plague has warned against the export of frog legs as it is likely to lead to the import of more insecticides and further aggravate pollution;

(b) if so, the reaction of Government thereto and the action taken in the matter;

(c) whether urbanised Bombay is exposed to plague risk as cautioned by Dr. Deoras; and

(d) the steps taken to contain the risk involved in the growing urbanisation and health hazard?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY PLANNING (DR. KARAN SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) to (d). A Statement is laid on the Table of the Sabha.

*Statement*

According to newspaper reports, Dr. P. J. Deoras is reproted to have stated in his address to the Indian Science Congress to the effect that;

(a) frogs eat insects and if they are killed for the sake of increasing the export of frog legs, more insecticides would have to be imported leading to more pollution, and

(b) with the rapid urbanisation of Bombay, the percentage of field rats in the city has increased causing a plague hazard.

2. The view that frogs play a significant role in the control of insect population is not yet substantiated, as insects are controlled in nature by a variety of animals. Even among frogs, the legs of only a certain species are exported. The question of importing